



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2015/पौष 17, 1936

No. 05]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2015/PAUSA 17, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2015

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टायरों के लिए टायर क्यूरिंग प्रेसेज के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की अंतिम समीक्षा की शुरुआत

सं. 15/22/2014-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995, के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/22/2004-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम द्वारा चीन जन.गण. में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित 'टायरों के लिए टायर क्यूरिंग प्रेसेज जिसे टायर वल्कनाइजर अथवा रबड़ प्रोसेसिंग मशीनरी के रूप में जाना जाता है' के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। तदनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क चीन जन.गण. (जिन्हें एतदपश्चात 'संबद्ध देश' कहा गया है) से 'टायरों के लिए टायर क्यूरिंग प्रेसेज जिसे टायर वल्कनाइजर अथवा रबड़ प्रोसेसिंग मशीनरी के रूप में जाना जाता है' (जिन्हें एतदपश्चात 'संबद्ध वस्तु' कहा गया है) के आयात पर 8 जनवरी, 2010 की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 01/2010 के माध्यम से लगाया गया था। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय के दिनांक 14 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/12 में पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र और परिधि से '6 दिन हल्की साइकिल टायर क्यूरिंग प्रेसेज' को बाहर कर दिया गया था।

समीक्षा के लिए अनुरोध

2. जबकि सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के संबंध में लगाया गया पाटनरोधी शुल्क यदि पूर्व में उसे समाप्त नहीं किया गया है, का शुल्क लगाने की तिथि से 5 वर्षों के समाप्त होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्राधिकारी को इस कार्रवाई की समाप्ति की तिथि से पूर्व उचित समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन अथवा क्षति होने की संभावना जारी रह सकती है।
3. और जबकि उपर्युक्त प्रावधान के संबंध में मै. लार्सन एंड ट्यूब्रो लि. ने वित्त मंत्रालय के दिनांक 8 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 01/2010 के माध्यम से संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की अंतिम समीक्षा करने के अनुरोध संबंधी एक विधिवत प्रमाणित आवेदन प्राधिकारी को दिया है और कंपनी ने संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग की है।
4. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट किया कि संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का पाटन पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में होने तथा उसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि होने की संभावना है। प्राधिकारी ने इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना की जांच की है। अतः आवेदक द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी का यह विचार है कि लागू पाटनरोधी शुल्कों के लिए अंतिम समीक्षा कार्रवाई की शुरुआत संबद्ध देश से उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संभावित पाटन से बचने तथा इस बात की जांच करने के लिए कि ऐसे शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता का परीक्षण करना उपयुक्त होगा कि यदि शुल्कों को हटाने की अनुमति दी जाती है तो घरेलू उद्योग को हानि होने की संभावना है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

5. मैसर्स लार्सन एंड ट्यूब्रो लि. (जिन्हें एतद्पश्चात् घरेलू उद्योग अथवा याचिकाकर्ता कहा गया है), जो संबद्ध वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक है, द्वारा यह आवेदन दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इसने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और यह संबद्ध देश के निर्यातक अथवा भारत में आयातक से संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है। इस कारण से याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका को दायर करने की स्थिति की आवश्यकता को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के तात्पर्य के भीतर 'घरेलू उद्योग' है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद '6 दिन हल्की साइकिल टायर क्यूरिंग प्रेसेज को छोड़कर टायर क्यूरिंग प्रेसेज है जिसे टायरों के लिए टायर वल्कनाइजर अथवा रबड़ प्रोसेसिंग मशीनरी के रूप में भी जाना जाता है'। टायर क्यूरिंग प्रेस एक मशीन है जिसका उपयोग किसी टायर के विनिर्माण के दौरान क्यूरिंग टायर के रूप में किया जाता है। एक मशीन का बीड आकार की श्रेणी के लिए उपयोग किया जा सकता है।
7. वर्तमान याचिका पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की अंतिम समीक्षा के लिए है। चूंकि प्रस्तावित जांच पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र प्रस्तावित जांच में वही है जो विगत में संपन्न मध्यावधि समीक्षा में उत्पाद का क्षेत्र है जिसमें '6 दिन हल्की साइकिल टायर क्यूरिंग प्रेसेज' को पाटनरोधी शुल्कों के क्षेत्र और परिधि से बाहर कर दिया गया था।
8. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु भौतिक एवं तकनीकी लक्षणों, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, मूल्य, वितरण एवं विपणन और शुल्क वर्गीकरण जैसे मानदंडों की दृष्टि से आयात किए गए उत्पाद के लिए समान वस्तु हैं। इन दोनों को तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। जांच के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के समान है।

संबद्ध देश

9. वर्तमान अंतिम समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

पाटन एवं क्षति होना

10. याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग को कम मूल्य पर बिक्री द्वारा क्षति उठानी पड़ रही है। यद्यपि क्षति अवधि के दौरान कोई आयात नहीं हुआ है फिर भी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में पाटन और क्षति होने की संभावना है। याचिकाकर्ता ने आगे यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए संबद्ध देश में क्षमताएं भारत में मांग की तुलना में बहुत अधिक हैं और तदनुसार प्राधिकारी द्वारा लगाए पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति देने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी का यह विचार है कि एक समीक्षा जांच को शुरू करने का औचित्य ठहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा पाटन होने का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

शुरूआत

11. एक समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर अपने आप को संतुष्ट करने के पश्चात, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन तथा घरेलू उद्योग को हानि होने की संभावना है, के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुरोध पर एक अंतिम समीक्षा शुरू करते हैं।

जांच की अवधि

12. इस जांच की अवधि अक्टूबर, 2013 - सितम्बर, 2014 (12 महीने) है। हानि का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, 3 पूर्व वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 तथा जांच अवधि के आंकड़ों पर जांच अवधि के रूप में विचार किया जाएगा। जांच अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच पाटन और हानि की संभावना का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है।

कार्यविधि

13. निम्नलिखित कार्यविधि का पालन किया जाएगा:-

- i. यह समीक्षा यथा संशोधित दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/22/2007-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित मूल जांचों के अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल करेगा।
- ii. इस नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधानों के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा में लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र एवं रूप में संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल
5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

समय-सीमा

16. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना अथवा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजा जाना चाहिए। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार, जिसका पता उपलब्ध नहीं है, भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नावली के उत्तर समेत प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को उनकी ओर से उसके संबंध में 'गोपनीयता' का दावा करने के मामले में दो अलग-अलग सेटों में उसे प्रस्तुत करना अपेक्षित है:-

(क) एक सैट गोपनीय रूप से अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि), और

(ख) दूसरा सैट अगोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

18. 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अनुरोधों में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अंकित होना चाहिए। ऐसे चिन्हांकन के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास ऐसे अनुरोधों का अन्य पक्षकारों को निरीक्षण करने देने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी। दोनों पाठों की साफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी के साथ-साथ प्रत्येक के पांच (5) सैटों में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होगी।

19. गोपनीय रूपांतरण में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वभाविक रूप से गोपनीय है और/या अन्य सूचना जिसे उस सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना या अन्य कारणों की वजह से दावा की गई गोपनीयता वाली सूचना के लिए सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संदिग्ध नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं लेंगे।

23. संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान करने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे.के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2015

Initiation Notification

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset review Anti-dumping investigation concerning imports of Tyre Curing Presses for Tyres originating in or exported from China PR

No. 15/22/2014-DGAD:— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti-dumping Duty on imports of “Tyre Curing Presses also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for tyres” originating in or exported from China PR, vide final findings of the Authority published vide Notification No. 14/22/2007-DGAD, dated 15th October, 2009. Accordingly, definitive anti dumping duties were imposed vide Ministry of Finance Notification No. 01/2010, dated 8th January, 2010 on import of “Tyre Curing Presses also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for Tyres” (hereinafter referred to as “subject goods”) from China PR (hereinafter referred to as “subject country”). Further, on the recommendation of designated authority, Ministry of Finance vide Notification No. 26/12, dated 14th May, 2012 excluded ‘6 day Light Bicycle Tyres Curing Presses’ from the scope and ambit of antidumping duties.

Request for Review

2. Whereas in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And, whereas, in terms of the above provision, M/s Larsen and Toubro Limited has approached the Authority with a duly substantiated application requesting for sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country vide Ministry of Finance Notification No. 01/2010, dated 8th January, 2010 and sought the continuation of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

4. The Authority has noted the submission of domestic industry that the dumping of the subject goods originating in or exported from subject country is likely to occur in case of cessation of anti-dumping duty causing injury to the domestic industry. The Authority has examined the data/information submitted by the domestic industry in this regard. The Authority, therefore, on the basis of prima facie evidence given by the applicant considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duties in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duties to offset likely dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to examine as to whether the injury to the domestic industry is likely to recur if the duties were allowed to cease.

Domestic Industry and Standing

5. The application has been filed by M/s Larsen and Toubro Limited (hereinafter referred to as the domestic industry or the petitioner), a major producer of the subject goods. The petitioner has claimed that it has not imported the

subject goods nor is related to exporters from the subject country or importers in India. It is noted from the data furnished by the petitioner that the production of petitioner constitutes a major proportion of total domestic production of subject goods in India. The petitioner therefore satisfies the requirement of standing to file the present petition and constitutes 'Domestic Industry' within the meaning of the AD Rules.

Product under Consideration and Like articles

6. The product under consideration in the present petition is "Tyre Curing Presses, excluding 6 day Light Bicycle Tyres Curing Presses", also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for tyres. Tyre Curing Press is a machine used for curing tyre during manufacturing of a tyre. One machine can be used for a range of bead sizes.

7. The present petition is for sunset review of the anti dumping duty earlier imposed. The proposed investigation being review of existing anti dumping duty, the scope of the product under consideration in the proposed investigation remains the same as the scope of the product in the last concluded Mid Term Review wherein '6 day Light Bicycle Tyres Curing Presses' was excluded from the scope and ambit of antidumping duties.

8. Further, the petitioner has claimed that the goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. After examination, the authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like articles to that imported from the subject countries.

Subject Countries

9. The country involved in the present sunset review investigations is China PR.

Recurrence of Dumping and Injury.

10. The petitioners have claimed that domestic industry continues to suffer injury by way of price underselling. Though there are no imports during the injury period, there is a likelihood of recurrence of dumping and injury in the event of revocation of anti dumping duty on subject goods from subject country. The petitioner has further claimed that capacities in subject country for subject goods are substantially huge in comparison to the demand in India and accordingly there is likelihood of recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry once the anti-dumping duties levied by the Authority are allowed to cease. The Authority considers that there is sufficient *prima facie* evidence of recurrence of dumping and injury caused to the domestic industry by dumped imports from subject country to justify initiation of a review investigation.

Initiation

11. Having satisfied itself on the basis of the positive *prima facie* evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a Sunset Review in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation

12. The Period of Investigation for this investigation is October, 2013 – September, 2014 (12 Months). For the purpose of analyzing injury, data of three previous years i.e. 2011-12, 2012-13, 2013-14 and POI will be considered as injury period. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure

13. The following procedure will be followed :

- i. The review will cover all aspects of the final findings of the original investigations published vide Notification No 14/22/2007-DGAD, dated 15th October, 2009 as amended.
- ii. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

Submission of Information:

14. The exporters in the subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce,
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street
New Delhi -110001

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit:

16. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification.

Submission of information on confidential basis

17. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- (a) One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

18. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

19. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

23. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File:

24. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

25. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J K DADOO, Designated Authority